



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 77]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 18, 2013/चैत्र 28, 1935

No. 77]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 18, 2013/CHAITRA 28, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2013

सं० 2 (आर.ई. 2013)/2009-2014

**फा. सं. 01/94/180/395/एम13/पीसी : 4.**—विदेश व्यापार नीति, 2009-14 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-I के अध्याय 4 में निम्नलिखित संशोधनों को अधिसूचित करते हैं। यह 18 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा।

(1) क्षेत्रीय प्राधिकारियों द्वारा निर्यातकों के लंबित आवेदनों को निपटान की सुविधा प्रदान करने के लिए, प्रक्रिया-पुस्तक खण्ड-1 के पैरा 4.20.5 को निम्नानुसार संशोधित करने का निर्णय लिया गया है :—

31 मार्च, 2004 को या पहले जारी किए गए प्राधिकार-पत्रों की कलबिंग अनुमत नहीं होगी। इसके अलावा, प्रक्रिया-पुस्तक खण्ड-1 के परिशिष्ट 30क के तहत शामिल प्राधिकार-पत्रों अथवा 18 महीने की निर्यात दायित्व अवधि से कम के प्राधिकार-पत्रों के कलबिंग की अनुमति नहीं होगी।

संशोधित उप-पैरा को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :—

"31 मार्च, 2004 को या पहले जारी किए गए प्राधिकार-पत्रों की कलबिंग अनुमत नहीं होगी। इसके अलावा, प्रक्रिया-पुस्तक खण्ड-1 के परिशिष्ट 30क के तहत शामिल प्राधिकार-पत्रों अथवा 18 महीने की निर्यात दायित्व अवधि से कम के प्राधिकार-पत्रों की कलबिंग की अनुमति नहीं होगी। तथापि, 1.4.2002 और 31.5.2012 के बीच जारी किए गए तथा 4.6.2012 को या पहले क्षेत्रीय प्राधिकारियों द्वारा प्राप्त किए गए अग्रिम लाइसेंसों/प्राधिकार-पत्रों की कलबिंग के लिए आवेदनों का निपटान, दिनांक 5.6.2012 को जारी संशोधित संस्करण/वार्षिक परिशिष्ट से पहले प्रक्रिया-पुस्तक खण्ड-I के प्रावधानों के अनुसार किया गया है बशर्ते कि इसमें सार्वजनिक सूचना सं० 79 दिनांक 13.10.2011 में निर्धारित शर्तों का पालन किया गया है"।

(2) टिप्पणी 3 में इलैक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया से संबंधित परिशिष्ट 21 ग के तहत विलोपन का संशोधन करने के लिए शब्द डीएफआईए को टिप्पणी के प्रथम वाक्य में 'अग्रिम प्राधिकार पत्र' के बाद जोड़ा जाता है।

**इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:** इससे निर्यातकों के 4.6.2012 तक प्राप्त अग्रिम प्राधिकार-पत्रों के कलबिंग करने के आवेदनों का निपटान करने में सुगमता होगी। दूसरा पैरा अन्य प्राधिकार-पत्रों के मामले में 200 रु० के अतिरिक्त आवेदन शुल्क की अदायगी के बाद निरस्त किए गए प्राधिकार-पत्रों के बदले दूसरा प्राधिकार-पत्र जारी करना सुगम बनाएगा।

अनुप के. पूजारी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****PUBLIC NOTICE**New Delhi, the 18<sup>th</sup> April, 2013**No. 2 (RE-2013)/ 2009-2014**

**F. No. 01/ 94/180/395/AM13/PC-4.**—In exercise of powers conferred under Paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2009-2014, the Director General of Foreign Trade hereby notifies the following amendments in Chapter 4 of the Handbook of Procedures (Volume I). This shall come into force from 18<sup>th</sup> April, 2013.

(1) In order to facilitate disposing of pending requests of the exporters by RAs, it has been decided to amend Para 4.20.5 of HBP v1 which reads as under :-

*No clubbing of authorisations issued on or before 31<sup>st</sup> March, 2004 shall be allowed. Further, no clubbing of authorisations covered under Appendix 30A of the HBPv-1 or authorisations with less than 18 months EOP shall be allowed.*

The amended Sub-para shall read as under [new portion in bold letters]:-

*“No clubbing of authorisations issued on or before 31<sup>st</sup> March, 2004 shall be allowed. Further, no clubbing of authorisations covered under Appendix 30A of the HBPv-1 or authorisations with less than 18 months EOP shall be allowed. **However, requests for clubbing of Advance Licences/Authorisations, issued between 1.4.2002 and 31.5.2012, and received by RAs on or before 4.6.2012 may be disposed of as per the provisions of HBP-v1 prior to issue of Revised Edition/Annual Supplement dated 5.6.2012, provided conditions stipulated in Public Notice No. 79 dated 13.10.2011 are adhered**”.*

(2) To rectify the omission under Appendix 21 C relating to PROCEDURE OF ELECTRONIC FUND TRANSFER in NOTE 3, the word ‘DFIA’ is being inserted after the words “Advance Authorisation” in the 1<sup>st</sup> sentence of the NOTE.

**Effect of this Public Notice :** This would facilitate disposal of pending requests the exporters for clubbing of advance authorisations where applications have been received upto 4.6.2012. The second para would facilitate issue of duplicate authorisation in lieu of cancelled authorisation after payment of only Rs.200 as additional application fee as in case of other authorisations.

ANUP K. PUJARI, Director General of Foreign Trade